



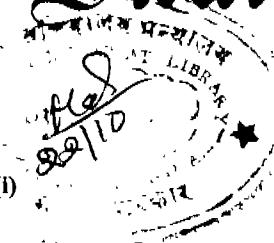
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 264]

No. 264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 1998/ आषाढ़ 26, 1920
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 1998/ASADHA 26, 1920

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1998

आयकर

सा.का.नि. 392 (अ).—चूंकि भारत गणराज्य की सरकार और बेलारूस गणराज्य की सरकार के भव्य आय पर और सम्पत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवर्त्तन की रोकथाम के लिए अनुबंधित समझौते के अनुच्छेद 30 के अनुसार उक्त समझौते को लागू करने के लिए दोनों की संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात 17 जुलाई, 1998 से लागू होगा।

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44 के द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा यह निर्देश देती है कि उपर्युक्त समझौते के सभी प्रावधान भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 10646/फा. सं. 501/7/92 वि.क.प्र.]

ए. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

आय तथा सम्पत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्त्तन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

बेलारूस गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और बेलारूस गणराज्य की सरकार आय तथा सम्पत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्त्तन को रोकने के लिए एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

- यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा सम्पत्ति (पूँजी) पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा ज्ञाहे ये कर किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. अचल सम्पत्ति अथवा अचल सम्पत्ति को छोड़कर किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्धमियों द्वारा अदा की गई मजदूरियों अथवा बेतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ कुल आय, कुल सम्पत्ति (पूँजी अथवा आय या सम्पत्ति (पूँजी) के तत्वों पर लगाए गए सभी करों की आय तथा सम्पत्ति (पूँजी पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया निम्नलिखित के अनुसार हैं :—

(क) भारत के मामले में :

- (i) आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है; और
- (ii) धनकर;
- (जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा); और

(ख) बेलारूस के मामले में :

- (i) आय तथा उद्यमों, संस्थाओं और संगठनों के लाभों पर कर;
- (ii) व्याप्तियों पर आय कर; और
- (iii) अचल सम्पत्ति पर कर;

(जिसे इसके बाद "बेलारूसी कर" कहा जाएगा) ।

4. यह करार किसी भी ऐसे समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "भारत"—पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें इसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायु मण्डलीय क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;
- (ख) "बेलारूस" पद से बेलारूस गणराज्य अभिप्रेत है और जब इसका भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तब इसमें वह राज्य क्षेत्र भी शामिल होगा जिस पर बेलारूस गणराज्य के कानूनों तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बेलारूस गणराज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार एवं क्षेत्राधिकार हों;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा बेलारूस गणराज्य अभिप्रेत है;

(घ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा बेलारूस कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय होगी, जिसके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड को निरुपित करती हो ।

(ङ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय तथा कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

(च) "कम्पनी" पद से अभिप्रेत :—

(i) भारत के मामले में, कोई निगमित निकाय अथवा अन्य सत्ता जिसे लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में समझा जाता हो;

(ii) बेलारूस के मामले में, कोई विधिक व्यक्ति अथवा कोई ऐसी सत्ता जिसे कर प्रयोजनों हेतु एक विधिक व्यक्ति के रूप में माना जाता हो;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचलित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचलित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :—

(i) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) बेलारूस के मामले में भूख्य राज्य कर समिति अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(झ) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(i) एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि;

(ii) कोई कानूनी व्यष्टि, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो;

(ज) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचलित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(ट) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित है;

(ii) बेलारूस के मामले में, वर्ष की पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक कैलेण्डर वर्ष ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू करने का संबंध है संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होने तक उनमें अपरिभाषित किसी ऐसे पद का वही अर्थ होगा जो अर्थ उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होगा ।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस प्रकार के प्रयोजनार्थ, “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद से अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उसके अधिवास, निगमन के स्थान, निवास, प्रबंध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यालयी के कारण कर लगता हो। परन्तु इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर उस राज्य में स्थित औरों से आय अथवा उसमें स्थित सम्पत्ति के बारे में ही उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. यहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तथा की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और अधिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित के केन्द्र स्थित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि उसे दोनों ही राष्ट्र अपना राष्ट्रिक समझते हों अथवा यदि वह दोनों में से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. यहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सके जहां इसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित हो, तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस कारार के प्रयोजनों के लिए “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआं, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के लिए निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई गोदाम जो दूसरों के लिए भण्डारण की सुविधाएं मुहैया करता हो;

(ज) कोई फार्म, बागान या अन्य ऐसा स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागान या इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों;

(झ) कोई बिक्री बाजार;

(ञ) कोई संस्थापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक औरों की खोज अथवा निष्कर्षण के लिए किया जाता हो;

(ट) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यावरणी क्रियाकलाप परन्तु ऐसा तभी होगा जब ऐसे स्थल, परियोजना अथवा क्रियाकलाप छह महीने से अधिक के लिए जारी रहते हों।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन हेतु किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का केवल दूसरे उद्यम द्वारा संसाधन किए जाने के प्रयोजनार्थ माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रम करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) केवल उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, अर्थात् कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक प्रकार का हो;

तथापि, उप-पैराग्राफ (क) से (च) तक के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां किसी उद्यम का उक्त उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई अन्य निश्चित स्थान हो।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य करता हो, वहां उस उद्यम का प्रथमोलिंगित संविदाकारी राज्य में ऐसे किन्हीं कार्यकलापों के संबंध में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा जो वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि ऐसे व्यक्ति को :

(क) उस राज्य में उस उद्यम की ओर से संविदाकारी करने का अधिकार प्राप्त हो और वह प्रायः उस अधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कार्यकलापों तक ही सीमित न हों, तब उसका यदि किसी निश्चित कारोबारी स्थान के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा तो इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अंतर्गत वह निश्चित कारोबारी स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा; अथवा

(ख) ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो किन्तु वह प्रायः प्रथमोलिंगित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिससे वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो।

5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा दूसरे अन्य ऐसे उद्यमों की ओर से किए जाते हों जो किसी ऐसे उद्यम को नियंत्रित करते हों अथवा किसी ऐसे उद्यम द्वारा नियंत्रित होते हों अथवा उस उद्यम के अनुरूप एक-समान नियंत्रण के अधीन हों तब उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के भीतर कोई स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं माना जाएगा।

6. यह तथ्य कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा इसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो केवल इसी आत से उन दोनों में से कोई भी कम्पनी एक दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

7. किसी उद्यम का एक संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तथा उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करना तभी माना जाएगा यदि वह उस राज्य में खनिज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा दोहन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करता हो अथवा उसके प्रयोग के लिए अथवा उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी को किराए पर देता हो।

8. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी भीमा उद्यम का पुनः भीमा करने के मामले को छोड़कर दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा यदि वह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम धसूल करता हो अथवा स्वतंत्र

हैसियत वाले किसी ऐसे एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों के लिए भीमा करता हो।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ यही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। जलायानों, नौकाओं, मोटर वाहनों तथा विमानों को अचल अथवा सम्पत्ति नहीं माना जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगी।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो कि निम्नलिखित के कारण उद्भूत होते हैं :

(क) वह स्थायी संस्थापन;

(ख) एक समान अथवा उसी प्रकार के माल अथवा पण्य-वस्तुओं की दूसरे राज्य में बिक्री, जैसे कि वे वस्तुएं जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेची जाती हैं; अथवा

(ग) एक समान अथवा उसी तरह के दूसरे राज्य में चलाए जा रहे अन्य कारोबारी क्रियाकलाप जैसे कि वे क्रियाकलाप जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से चलाए जाते हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से कारोबार करता हो। वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई भिन्न स्वतंत्र उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, जहां ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा यह उस राज्य के उपर्युक्तों के अनुसार तथा उसके कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए पात्र माल अथवा पर्याप्त वस्तुओं की खरीद की गई है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहां आय की मदों में लाभ की वे मदें शामिल हैं जिनका इस प्रकार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपर्युक्त इस अनुच्छेद के उपर्युक्तों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

अन्तरराष्ट्रीय यातायात

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के लाभों पर, जैसा भी मामला हो, केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपर्युक्त किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपर्युक्त ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभों से तात्पर्य, जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों अथवा पट्टाधारकों अथवा घार्टर-कर्त्ताओं द्वारा क्रमशः समुद्र अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन, माल अथवा पर्याप्त-वस्तुओं के परिवहन से किसी उद्यम को प्राप्त लाभ से होगा। इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे :

- (क) दूसरे उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन हेतु टिकटों की बिक्री;
- (ख) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के संबंध में प्रयुक्त आधानों का प्रयोग, अनुरक्षण अथवा किराया (जिसमें आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलर, नैकारे और इससे संबंधित उपस्कर सम्मिलित हैं);
- (ग) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन हेतु प्रासंगिक जलयानों अथवा वायुयानों का किराया; और

(घ) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अन्य कार्यकलाप।

अनुच्छेद-9

सहयोगी उद्यम

जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई जाने वाली शर्तों से भिन्न होती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकता।

अनुच्छेद-10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसको लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) यदि हितभागी स्वामी एक कम्पनी है जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के शेयरों के कम से कम 25 प्रतिशत पर प्रत्यक्षतः स्वामित्व है तो लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभांशों के मामले में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “लाभांश” पद का अर्थ शेयरों अथवा अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभों में भागीदारी के ऋण-दावे नहीं होने तथा अन्य ऐसे अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के

माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरे राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही कम्पनी के अवितारित लाभों पर, अवितारित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितारित लाभपूर्ण रूप से अथवा अशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद-11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी,

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी अशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :

- (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
- (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक अथवा कोई अन्य बैंक या सरकारी वित्तीय संस्थाएं जिन पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति होती है।

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक उस संविदाकारी राज्य में कर से छुट तब प्राप्त होगी जब यह ब्याज उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी

है अशर्ते कि जिस सेन-देन के कारण ऋण-दावा उद्भूत होता है उसे प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य को सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

4. अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “ब्याज” शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें कर्जदार के लाभों में भागीदारी को कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो, और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। बिलम्ब अदायगी के लिए जुर्मानों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित ऐसे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से करोकर करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध यथा स्थिति लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब ब्याज देने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य को कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किसी जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जो ऐसा विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध के बल अंतिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के आतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और

उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सके गा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “रायलिट्यों” पद से अभिप्रेत है किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमा-फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियाँ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पद का अभिप्राय तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित कोई प्रबंध कार्य, तकनीकी अथवा परामर्श सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां शामिल हैं परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्थानी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें, रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायलिट्यों अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती हो, तब ऐसी रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्थानी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती

है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध के बल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होगे। ऐसे मामलों में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13

पूँजीगत अभिलाभ (सम्पत्ति के अन्तरण से लाभ)

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सके गा।

2. ऐसी सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति को छोड़कर, के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति को छोड़कर, के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोगनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति को छोड़कर, के अन्तरण के प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सके गा जिसका अन्तरणकर्ता एक निवासी है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धान्तः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कम्पनी के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर जो कि एक संविदाकारी राज्य की निवासी हैं, उस राज्य में कर लग सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सके गा जिसका अन्तरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद-14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सके गा, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी:

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके उत्तरने की अवधि अथवा अधिकारी किसी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों तक अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा कार्य विकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-15

परावलम्बिक वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोत्तिक राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

- (क) प्राप्तकर्ता किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है; और
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किसी गए कियो नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस स्थान इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी हैं, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में साधू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए संविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों द्वारा अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की लोक-निधियों द्वारा पूर्णतया उसकी सहायता की जाती हो अथवा क्रियाकलाप संविदाकारी राज्यों के बीच सांस्कृतिक अथवा खेलकूद सहयोग अनुबंध की रूपरेखा के अंतर्गत निष्पादित किए गए हों। ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधीय होगी जिसको मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी हैं।

अनुच्छेद-18

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पैशान से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :

- (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है, अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूचित कोष द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पैशान पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि ऐसी पैशान पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तभी लग सकेगा यदि व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेदों 15, 16 और 19 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पैशान पर लगाये जाएं।

अनुच्छेद-19

गैर सरकारी पेशन तथा वार्षिकिया

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतरी स्त्रों से प्राप्त अनुच्छेद 18 में उल्लिखित किसी पेशन से भिन्न किसी पेशन अथवा किसी वार्षिकी पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर सकेगा।

2. “पेशन” पर से पिछली सेवाओं के लिए परिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतिपूर्ति के रूप में दो जाने वाली आवधिक अदायगी अधिग्रेत है।

3. “वार्षिकी” पद से जीवन काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने की आव्याता के अंतर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर देय निश्चित धनराशि अधिग्रेत है।

अनुच्छेद-20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां, और

(ख) उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त उतनी रकम का प्राप्त प्रतिफल जो उस रकम से अधिक न हो, जिस पर किसी वित्तीय वर्ष में उस अन्य संविदाकारी राज्य में कानूनों के तहत कर से छूट प्राप्त होती है, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे तौर पर संबंधित हो या उसके भरण-पोषण के लिए किया जाता हो।

2. इस अनुच्छेद के लाभ के बल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणता अपेक्षित हो परन्तु किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद-21

प्रोफेसर, अध्यापक और शोध अध्येता

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरी ऐसी संस्था में शिक्षण अथवा शोध कार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था, उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए उसको प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह उक्त वित्तीय वर्ष में उस संविदाकारी राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उक्त वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व दौरा करता है।

अनुच्छेद-22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दें, जहाँ-कहाँ वे उद्भूत होती हैं, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थानी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-23

सम्पत्ति (पूँजी)

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निसफित पूँजी, जो कि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस पर दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति के अंश के रूप में अचल सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति द्वारा अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित अचल सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध होती है, निरूपित सम्पत्ति (पूँजी) पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों और वायुयानों द्वारा निरूपित सम्पत्ति (पूँजी) पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय जलयानों के परिवहन में लगी हुई नावों द्वारा निरूपित (पूँजी) पर और ऐसे जलयानों या वायुयानों के संचालन से संबंधित अचल सम्पत्ति से अन्य सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूँजी के बल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी जिसका कि ऐसे जलयानों, वायुयानों अथवा सम्पत्ति का स्थानी एक निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की सम्पत्ति (पूँजी) के सभी अन्य तत्वों पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान मामलों के अधिशासित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जहाँ इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किए जाते हैं।

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जायगा:

जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो अथवा वह ऐसी पूँजी का मालिक हो जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार बेलारूस गणराज्य में कर लगाया जा सकता है वहाँ पर भारत उस निवासी की उस आय पर बेलारूस गणराज्य में अदा की गई आयकर के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा वह प्रतक्षत: दो जाए अथवा कटौती द्वारा तथा बेलारूस गणराज्य में अदा किए गए सम्पत्ति (पूँजी) कर के बराबर की रकम पर उस निवासी की पूँजी पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, दोनों में से किसी भी स्थिति में ऐसी कटौती आयकर अथवा पूँजी कर के उस अंश से (जो कटौती की अनुमति दिए जाने से पहले संगणित की जाती हैं) अधिक नहीं होगी जो उस आय अथवा पूँजी से उद्भूत होती हैं जैसी भी स्थिति हो, जिस पर बेलारूस गणराज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. बेलारूस गणराज्य के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :

जहाँ बेलारूस गणराज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहाँ पर बेलारूस गणराज्य उस निवासी की उस आय पर भारत में अदा की गई आयकर के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा तथा भारत में अदा किए गए सम्पत्ति (पूँजी) कर के बराबर की रकम पर उस निवासी की पूँजी पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती आयकर अथवा पूँजी कर के उस अंश से, जो कटौती की अनुमति दिए जाने से पहले संगणित की जाती है, अधिक नहीं होगी जो उस आय अथवा पूँजी से जैसी भी स्थिति हो, उद्भूत होती हैं, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर शामिल समझा जाएगा जो कि संविदाकारी राज्य के कानूनों के अधीन दिए जाने वाले उन कर प्रोत्साहनों के न होने पर देय होता और जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

5. ऐसी आय, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता, उसे उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर के दर की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद 25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी कराधान को अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा, जो दूसरे राज्य में राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जा रहे अथवा लगाए जा सकने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर हों।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे के उद्यमों पर एक-समान कार्यकलालों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के प्रथमोलिलिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के साथों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो कि उससे अधिक हो जो प्रथमोलिलिखित संविदाकारी राज्य के वैसी ही उद्यम के साथों पर लगाया जाता है और नहीं इसका यह अर्थ होगा कि यह इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के विपरीत हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी आत का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह वाध्यकर है कि वह उन व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत हूँ, राहत, कटौतियाँ अथवा घटौतियाँ मंजूर करे, जो कि कानून द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहाँ के निवासी हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वाभित्व में अथवा नियंत्रण में हैं, प्रथमोलिलिखित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत भारपूर हो, जो उस प्रथमोलिलिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं शर्तों के तहत लागू हो सकती हो।

5. इस अनुच्छेद में, “कराधान” पद का आशय उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

6. ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, वहाँ एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त व्याज, रायलिट्यों और अन्य संवितरणों को ऐसे उद्यमों के कर योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य माना जाएगा मानो कि उन्हें प्रथमोलिलिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था। इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया कोई ज्ञान ऐसे उद्यम की कर योग्य पूँजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य माना जाएगा मानो कि उन्हें प्रथमोलिलिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था।

अनुच्छेद-26

पारस्परिक करार स्थिति

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य कोई निवासी यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अनुरूप नहीं है तो वह उन संविदाकारी राज्य के देशीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों का ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप उस पर कर लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार हेतु जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के देशीय कानूनों में कोई समय सीमा बर्यों न हो।

3. इस करार के अर्थ-निरूपण में अथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई या शंका उत्पन्न होती है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे जिन्हें इस करार में नहीं दिया गया है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोगनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का भौतिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त लगे तो विचारों का आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से हो सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद-27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वयित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तब कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना भी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें व्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रबलन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण

करने से सम्बद्ध हों, जो करार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक व्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा व्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों, सूचना तथा दस्तावेजों की सूची को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है। सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर किया जाएगा।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निष्पत्तिविहित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हैं;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों को सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-28

वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य एक दूसरे को उन मामलों में करों की वसूली हेतु सहायता एवं सहयोग देने का वचन देते हैं जहां अनुरोध करने वाले राज्य के कानूनों के अनुसार कर निश्चित तौर पर देय हो।

2. वसूली को लागू किए जाने हेतु अनुरोध के मामले में, दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य के कर दावे को जिन्हें अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन हेतु स्वीकार कर लिया जाएगा जिसे अनुरोध किया जाता है और इसकी उस राज्य में करों के प्रवर्तन एवं वसूली हेतु प्रवृत्त कानूनों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. भारतीय कर के मामले में, अनुरोध केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा बेलारूस गणराज्य की राज्य कर समिति को भेजा जाएगा और इसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र भेजा जाएगा जो भारतीय कानून द्वारा यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित हो कि करों का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और ये करदाता से देय हैं।

4. बेलारूस के मामले में, अनुरोध बेलारूस गणराज्य की राज्य कर समिति द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग को भेजा जाएगा और इसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र भेजा जाएगा जो बेलारूस गणराज्य के कानून द्वारा यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित हो कि करों का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और ये करदाता से देय हैं।

5. जहां कर दावे को अपील अथवा किसी अन्य कार्यवाही का मुश्ह होने के कारण अन्तिम रूप न दिया गया हो, वहां एक संविदाकारी राज्य अपने राजस्व हितों की रक्षा करने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी ओर से ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत विधि संगत हो।

6. किसी करदाता से देय करों की वसूली के लिए सहायता का अनुरोध तभी किया जाएगा यदि अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस कर दाता के पास करों की वसूली हेतु पर्याप्त सम्पत्तियां उपलब्ध न हों।

7. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में जिस संविदाकारी राज्य में कर की वसूली की जाती है वह संविदाकारी राज्य इसके तुरन्त बाद इस प्रकार वसूल की गई राशि उस संविदाकारी राज्य को लौटा देगा जिसने इसके लिए अनुरोध किया था परन्तु उसे उन खर्चों की प्रतिपूर्ति का हक होगा, यदि कोई हो, जो ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान किए गए हों, और यह प्रतिपूर्ति इस सीमा तक की जाएगी जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में पारस्परिक सहमति हो गई हो।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक और कोंसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कोंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 30

प्रबुत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा किए जाने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप से एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति के तीस दिन बाद प्रभावी हो जाएगा।

3. इस करार के उपबंध निम्न प्रकार से प्रभावी होंगे :

(क) भारत में,

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को धारित पूँजी के संबंध में।

(ख) बेलारूस में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्राप्त आय की राशि पर स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में प्रभार्य ऐसे करों की सम्पत्ति (पूँजी) पर करों और आय पर अन्य करों के संबंध में।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी को जाएगा :

(क) भारत में,

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्राप्त आय की राशि पर स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में।

(ख) बेलारूस में,

(i) जिस वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में प्रभार्य ऐसे करों की अन्य आय पर, करों अथवा सम्पत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में प्रभार्य ऐसे करों की अन्य आय पर, करों अथवा सम्पत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नीं सौ सत्तानवे के सितंबर माह के 27वें दिन, हिन्दी, बेलारूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। कि सी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

(पी. चिदम्बरम्)

वित्त मंत्री

बेलारूस गणराज्य की

सरकार की ओर से

(मिखाइल मारीनिच)

विदेशी वित्तीय संबंध मंत्री

प्रोतोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और बेलारूस गणराज्य की सरकार ने आय और सम्पत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में दोहरे करधान के परिहार और राजस्व अपबंधन को रोकने के लिए दोनों सरकारों के बीच होने वाले करार पर नई दिल्ली में 27 सितम्बर, 1997 को हस्ताक्षर करने वेष्ट लिए निम्नलिखित उपबंधों पर करार किया है जो कि उक्त करार के अभिन्न अंग होंगे।

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, करार में यथा-प्रयुक्त "राजनैतिक उप-प्रभाग" पद के बल भारत के लिए लागू होगा।

2. अनुच्छेद 4 के संदर्भ में, यह माना जाता है कि "प्रभावी प्रबंध-स्थान" को स्थापित करते समय, जैसा कि अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 में प्रयुक्त किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ जिन परिस्थितियों, जिन्हें ध्यान में रखना है, वे स्थान हैं जहां से किसी कम्पनी का वास्तव में प्रबंध और नियंत्रण किया जाता है, जहां किसी कम्पनी के प्रबंधन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण नीतियों पर उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया जाता है और जो स्थान आर्थिक और कार्यात्मक दृष्टि से किसी कम्पनी के प्रबंधन में मुख्य भूमिका अदा करता है और वह स्थान जहां संगत लेखा बहियां रखी जाती हैं।

3. इस करार के प्रयोजनार्थ, यह माना जाता है कि "नियंत्रण" पद में किसी व्यक्ति को नियमित रूप से उपलब्ध एक नियंत्रण स्थान जैसे कोई कार्यालय अथवा कोई कमरा अथवा कोई अन्य स्थान शामिल है। जिसके माध्यम से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यकलाप पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किए जाते हैं।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ सतानवे के सितंबर माह के 27वें दिन, हिन्दी, बेलारूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। किसी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।

ह०/-

भारत गणराज्य की	बेलारूस गणराज्य की
सरकार की ओर से	सरकार की ओर से
(पी. चिदम्बरम्)	(मिखाइन मारीनिच)
वित्त मंत्री	विदेशी वित्तीय संबंध मंत्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1998

INCOME TAX

G. S. R. 392(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property (capital) shall enter into force on the Seventeenth day of July, 1998, in accordance with Article 30 of the said Agreement, thirty days after the receipt of later of notifications by both the Contracting States to each other of completion of the procedure required by their respective laws for bringing into force of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 10646/F.No. 501/7/92-F.T.D.]

A.N. PRASAD, Jt. Secy.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS

For the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property (Capital)

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Belarus desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property (capital) have agreed as follows:

Article 1 PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on property (capital) imposed on behalf of a Contracting State or of its political sub divisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on property (capital) all taxes imposed on total income, on total property (capital) or on elements of income or of property (capital) including taxes on gains from the alienation of immovable property or property other than immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The taxes to which this Agreement shall apply are in particular :

(a) in India :

- (i) the income-tax including any surcharge thereon; and
- (ii) wealth tax

(hereinafter referred to as "Indian Tax"); and

(b) in Belarus :

- (i) the tax on income and profits of enterprises associations and organisations;
- (ii) the income tax on individuals; and
- (iii) the tax on immovable property (hereinafter referred to as "Belarusian tax").

4. The Agreement shall apply also to any similar or substantially identical taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3 above. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with International law and the U. N. Convention on the law of the Sea ;
- (b) the term "Belarus" means the Republic of Belarus and when used in a geographical sense, means, the territory over which the Republic of Belarus exercises under the laws of the Republic of Belarus and in accordance with international law sovereign rights and jurisdiction ;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean, as the context requires, India or the Republic of Belarus ;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Belarusian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes ;
- (e) the term "person" includes an individual, a company, a body of person and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term "company" means :
 - (i) in India, any body corporate or other entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force ;
 - (ii) in Belarus, any legal person or any entity which is treated as a legal person for tax purposes ;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;

(h) the term "Competent authority" means :

- (i) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative ;
- (ii) in the case of Belarus, the State Tax Committee or its authorised representative ;
- (i) the term "national" means :
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State ;
- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.
- (k) the term "fiscal year" means :
 - (i) in the case of India, "previous year" as defined under Section 3 of the Income Tax Act, 1961 ;
 - (ii) in the case of Belarus, the calendar year from 1st day of January to 31st day of December of the year.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, place of incorporation, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. However, this term does not include any person who is liable to tax in that State only in respect of income from sources in that State or property situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests) ;

- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined or if he does not have permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national ;
- (d) if each State considers him as its own national or if he is not a national of either of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 if a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated can not be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others ;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation, or related activities are carried on ;
- (i) a sales outlet ;
- (j) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources ;
- (k) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith only if such site, project or activity lasts for more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purposes of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

However, the provisions of sub-paragraphs (a) to (f) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person :

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph ; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, a commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

8. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies.

Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. Ships, boats, motor vehicles and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply to income from immovable property of an enterprise and also to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to :

- (a) that permanent establishment ;
- (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment ; or
- (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might make if it were a separate independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and acting wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase of goods or merchandise by that permanent establishment for the enterprise.

5. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there are good and sufficient reasons to the contrary.

6. Where the profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

International Traffic

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation on ships or aircraft in international traffic, as the case may be, shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise from the transportation by sea or air, respectively, of passengers, mail, livestock, goods or merchandise carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft. This will also include :

- (a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises ;
- (b) the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transportation of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic ;
- (c) the rental of ships or aircraft incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic ; and
- (d) other activity directly connected with operation of ships or aircraft in international traffic.

Article 9 Associated Enterprises

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10 Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends ;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares under the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding, in respect of which, the dividends are paid, is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 7 or 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other state.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

- (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State or any other bank or Governmental financial institutions that may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person, other than a person referred to in subparagraph (a), who is a resident of the other Contracting State, provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, its political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties and Fees for Technical Services

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that state, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematography films or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall

be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital Gains (Gains from Alienation of Property)

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of property other than immovable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of property other than immovable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or property other than immovable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable

only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State ; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in a period of twelve months; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve months; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by the enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, such income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is supported wholly by public funds of one or both of the Contracting States of political subdivisions or local authorities thereof or the activity is exercised within the framework of cultural or sports cooperation agreement between the Contracting States. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

GOVERNMENT SERVICE

1. (A) Remuneration, other than pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (A) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxed only in that State;

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 19

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State for an amount not exceeding the amount which is exempt from tax under the laws of the other Contracting State for any fiscal year; provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, or other similar institution in that Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of Contracting State if he is resident in that Contracting State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately fiscal year.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right of property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 23

PROPERTY (CAPITAL)

1. Property (Capital) represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Property (Capital) represented by property other than immovable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by property other than immovable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Property (Capital) represented by ships and aircraft operated in international traffic or by boats engaged in inland waterways transport and by property other than immovable property pertaining to the operation of such ships, boats and aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the owner of such ships, boats, aircraft or property is a resident.

4. All other elements of property (Capital) or a resident of a Contracting State shall be taxed only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting State shall continue to govern the taxation of income and property (Capital) on the respective Contracting State except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

2. In the case of India, double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Republic of Belarus, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the Republic of Belarus whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the property (capital) tax paid in the Republic of Belarus. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income-tax or capital tax as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in the Republic of Belarus.

3. In the case of the Republic of Belarus, double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of the Republic of Belarus derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, the Republic of Belarus shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India; and as a deduction from tax on the property (capital) of that resident, an amount equal to the capital tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or property (capital) tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the property (capital) which may be taxed in India.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

5. Income which in accordance with the provisions of this Agreement, is not to one subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State, to other or more burdensome taxation or may requirement connected therewith, than the

taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

6. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11 of paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxation profits of such enterprises, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxation capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first mentioned State

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not, in accordance with this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting States of which he is a resident, or of his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of

which he is a national.. The case must be presented within three years from the date of the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State for the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including domestics) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting States shall be treated as actor in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques, the list of information and documents concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance. The exchange of information or documents shall be on request of the competent authorities of the Contracting States.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed as to impose on a Contracting State the obligation :

(a) to carry out administrative measures at variance with the law or administrative practice of that or the other Contracting State;

(b) to supply information or domestic which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret, or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy

Article 28

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Agreement relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the State making the request.

2. In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue to the State Tax Committee of the Republic of Belarus and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

4. In the case of Belarusian tax, the request will be sent by the State Tax Committee of the Republic of Belarus to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, in India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of the Republic of Belarus to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. Where that tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the

Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of actual costs, if any, incurred in the course of rendering assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the Contracting States.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Agreement shall have effect:

(a) in India:

(i) in respect of income arising in any fiscal year beginning or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

(b) in Belarus :

(i) in respect of taxes withheld at source on amounts of income, derived on or after 1st of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; and

(ii) in respect of other taxes on income and taxes on property (capital) to such taxes chargeable in any taxable year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by given notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of

five years from the date of entry into force of the Agreement.
In such event, the Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India,
 - (i) In respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
 - (ii) in respect of capital which is held at the expiry of any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.
- (b) in Belarus,
 - (i) in respect of taxes withheld at source, to amounts of income derived on or after 1st of January in the calendar year next following the year in which the notice is given;
 - (ii) in respect of other taxes on income or taxes on property (capital) to such taxes chargeable in any taxable year beginning on or after 1st of January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi, this 27th day of September, 1997 in Hindi, Belarusian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the

Republic of India
(P. Chidambaram)
Minister of Finance

For the Government of the

Republic of Belarus
(Mikhail Marinich)
Minister of External
Economic Relations

PROTOCOL

The Government of Public of India and the Government of the Republic of Belarus have agreed at the signing at New Delhi on 27th September, 1997 of the Agreement between the two states for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property (capital) upon the following provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

1. For purposes of this Agreement, the term "political subdivision" as used in the Agreement shall be applicable to India only.
2. With reference to Article 4, it is understood that when establishing the "place of effective management" as used in paragraph 3 of Article 4, circumstances which may, interalia, be taken into account are the place where a company is actually managed and controlled, the place where the decision making at the highest level on important policies essential for the management of company takes place, the place that plays a leading part in the management of a company from an economic and functional point of view and the place where the relevant accounting books are kept.
3. For purposes of this Agreement, it is understood that the term "fixed base" includes a fixed place such as an office or a room or any other place regularly available to him through which the activity of a person performing independent personal services is wholly or partly carried on.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto have signed this Protocol.

Done, in duplicate, at New Delhi, this 27th day of September, 1997 in Hindi, Belarusian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of
The Republic of India
(P. Chidambaram)
Minister of Finance

For the Government of
The Republic of Belarus
(Mikhail Marinich)
Minister of External
Economic Relations